P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-2* May - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत–चीन सम्बन्ध : एक समीक्षात्मक विश्लेषण

India-China Relations: A Critical Analysis

Paper Submission: 20/05/2020, Date of Acceptance: 29/05/2020, Date of Publication: 30/05/2020

बनवारी लाल मैनावत
सह–आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
गंगापुर सिटी (स.मा.)
राजस्थान, भारत

सारांश

प्राचीन काल से ही भारत के चीन के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध रहे है। भारत की नीति सदैव शांतिपूर्ण, सह–अस्तित्व, सहयोगात्मक तथा पंचशील सिद्धान्तों पर आधारित रही है। 1949 के बाद चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। शुरू में भारत–चीन सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे किन्तु कुछ समय बाद में ही चीन ने आक्रामक, साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर लिया। जिसमें ''चारा और छड़ी'' नीति, ''मोतियों की माला'' नीति तथा हिन्द–प्रशान्त सागर में वर्चश्व की नीति को बढावा दिया है। चीन–ऐसिया में एकाधिकार चाहता है। उसे लगता है कि भारत एक मात्र देश है जो कि प्रतिद्वन्दिता कर सकता है। इस कारण वह शक्ति प्रदर्शन, सीमा पर तनाव, भारत की धेराबन्दी आदि कूटनीतिक चालें चलता रहता है। ऐसिया के अन्य देशों को भी अपनी शक्ति बल पर आँखे दिखाता रहता है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में भारत की आर्थिक प्रगति, राजनीतिक एवं सामरिक सुदृढ़ता चीन के लिये चुनौती बनी हुई है। किन्तु दूसरी तरफ भारत का आर्थिक बाजार उसके आकर्षण का केन्द्र भी है। इस कारण 90 के दशक एवं सन् 2000 के बाद चीन ने भारत के साथ आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सम्बन्ध बढ़ाये है। समयानुसार भारत ने भी अपने सम्बन्धों को गति दी है। किन्तु सामरिक, परमाणविक, सीमा विवाद क्षेत्र में आज भी स्थाई समाधान नही हो सका है। सीमा पर अक्सर तनाव का वातावरण बन जाता है। ''सीमा विवाद जो तनाव का बहुत बड़ा कारण है, उसके समाधान हेतु ठोस व प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

Since ancient times, India has had commercial, cultural and religious relations with China. India's policy has always been based on the principles of peaceful, co-existence, cooperative and Panchsheel. Communist rule was established in China after 1949. Initially, India-China relations were friendly, but soon after, China followed an aggressive, imperialist and expansionist policy. In which "fodder and stick" policy, "beads of pearl" policy and the policy of domination in the Indo-Pacific Sea have been promoted. China wants monopoly in Asia. He feels that India is the only country that can compete. Due to this, he keeps on displaying power, tensions on the border, diplomatic moves of India etc. Other countries of Asia also show their eyes on their strength. In the current era of globalization, India's economic progress, political and strategic strength remains a challenge for China. But on the other hand India's economic market is also its center of attraction. Because of this, China has increased economic, commercial, cultural and educational relations with India after 90s and 2000s. India has also given momentum to its relations over time. But in the strategic, nuclear, border dispute area, there is still no permanent solution. An atmosphere of tension is often created at the border. "There is a need to take concrete and effective steps to resolve the border dispute which is a major cause of tension."

मुख्य शब्द : भारत–चीन सम्बन्ध, सीमा विवाद, आर्थिक, व्यापारिक सम्बन्ध, तनाव, आयात–निर्यात, डोकलाम, शिपकीदर्रा, लिपिलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, अक्साई चीन, कराकोरम, तिब्बत, वैश्वीकरण, सामरिक, मोतियों की माला, मुर्गी की गर्दन क्षेत्र, राजनीतिक, बंदरगाह, हिन्द महासागर, प्रशान्त क्षेत्र, परमाणु समझौता, चीन–पाक कोरीडोर, यात्रा, शिखर वार्ता, समझौता, सहअस्तित्व, आदान–प्रदान आदि।

India-China Relations, Border Dispute, Economic, Trade Relations, Tension, Import-Export, Doklam, Shipkidarra,

Lipkhil Pass, Nathula Pass, Aksai China, Karakoram, Tibet, Globalization, Strategic, Pearl Beads, Hen Neck Area, Political , Ports, Indian Ocean, Pacific Region, Nuclear Agreement, Sino-Pak Corridor, Travel, Summit, Agreement, Coexistence, Exchange etc

प्रस्तावना

भारत–चीन दोनो पड़ौसी एवं विश्व के दो बड़े विकासशील देश है। दोनो के बीच लम्बी सीमा रेखा है। इन दोनो के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, आर्थिक तथा धार्मिक सम्बन्ध रहे है। भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार चीन की भूमि पर हुआ है। चीन के लोगो ने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों यथा – नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय को चुना था। क्योंकि उस समय संसार में अपने तरह के यही दो विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र थें। उस समय यूरोप के लोग जंगली अवस्था में थे। 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। तथापि दोनो देशो के बीच मैत्री सम्बन्ध बने रहे। जापान के साम्राज्यवाद के विरूद्ध भारत ने चीन के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी एवं पंचशील के प्रति दोनो देशो ने आस्था प्रकट की थी। 1950 में ही भारत ने चीन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये तथा चीनी लोक गणराज्य को मान्यता देने वाला भारत प्रथम गैर समाजवादी देश था। चीन में 1949 में साम्यवाद की सत्ता स्थापित हुई तब से लेकर 1957 तक भारत–चीन सम्बन्ध सौहार्द पूर्ण रहे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि 1950 में जब चीन ने तिब्बत को हड़पा तो भारत ने इसे मौन स्वीकृति देने के साथ ही यातुंग तथा ग्यान्तसे क्षेत्रो से अपने राजनीतिक अधिकार भी हटा लिए जो कि अंग्रेजो से भारत को विरासत में मिले थे। तिब्बत से भारत ने अपने देशीय अधिकारों को चीन को सौप दिया। 1954 में व्यापारिक समझौते हुए एवं पंचशील के सिद्धान्तोपर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के हस्ताक्षर हुए थे। किन्तु 1958 के बाद दोनो देशों के मध्य तनावपूर्ण सम्बन्ध हो गये और निरन्तर 1978 तक चलते रहें। इस बीच चीन द्वारा खम्बा क्षेत्र के विद्रोह को क्रूरता से दबाना व दलाई लामा का भारत में शरण लेना, 1959 में चीन द्वारा सीमा विवाद पैदा करना तथा 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण किया जाना, इसके अलावा भारत–पाक युद्ध में पाक की तरफ चीन का रूझान होना आदि मामलो ने दोनो दोशों के बीच शत्रुता के सम्बन्ध बना दिये। चीन ने भारतीय क्षेत्र अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त पी ओ के में कराकोरम सड़क बनाली गई और बड़े हिस्से को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। 1978 के बाद सम्बन्धों में कुछ बदलाव आने लगा। एक–दूसरे के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलों का आवागमन शुरू हुआ। 1979 में भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने चीन की यात्रा की, किन्तु उसी दौरान चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया, इस कारण विदेशमंत्री बाजपेई को यात्रा के बीच में से ही लौटकर आना पड़ा था। इस प्रकार सम्बन्धों मे अधिक सुधार नहीं हो पाया था। हालांकि 1981 में चीन विदेश मंत्री हुआफेंग ने भारत की यात्रा भी की थी और मानसरोवर जाने का रास्ता खोला गया। फिर भी सीमा विवाद, अरूणाचल प्रदेश, अक्छाई चीन मामलों के चलते सम्बन्धों की धीमी गति रही थी।

अध्ययन का उद्देश्य

वैश्वीकरण, उदारीकरण के युग में भारत–चीन सम्बन्धो का समीक्षात्मक विश्लेषण, दोनो के मध्य अनसुलझे मुद्दों की और ठोस कदम बढ़ाने हेतु सुझाव व संकेत देना। आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धों का विश्लेषण।

विषय विस्तार

1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने लम्बे समय बाद चीन की यात्रा की और दोनो तरफ से अतीत को भूल कर सम्बन्धों की नई शुरूआत करने पर सहमति बनी। इस दौरान आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकि तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बढाने के लिए संयुक्त आयोग गठन किये जाने की सहमति बनी, साथ ही दोनो देशों के मध्य सीधी टेलिफोन सेवा भी शुरू की गई। 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली फेंग ने उच्च स्तरीय दल के साथ भारत की यात्रा की। इसमें समझौता हुआ कि संधाई तथा मुम्बई में एक–दूसरे का वाणिज्य दूतावास खोला जायेगा, व्यापार, अन्तरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बढायेंगे तथा सीमा विवाद शांतिपूर्ण तरीके से निपटायेंगे। तिब्बत को भारत ने चीन का स्वायन्त क्षेत्र मान लिया। 1992 में भारतीय राष्ट्रपति बैंकटरमन ने चीन की यात्रा की और चीनी राष्ट्रपति यांग शाकुन ने अतीत के मित्रवत, ''हिन्दी–चीनी भाई–भाई'' सम्बन्धों की याद दिलाई तथा भविष्य में भी बनाये रखने की बात कही। इसी क्रम में 1993 में भारतीय प्रधानमंत्री नरसिंह्मा राव ने चीन की यात्रा की और भारत–चीन के मध्य सीमा क्षेत्र की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाये रखने का समझौता हुआ। समझौते को लागू करने के लिए संयुक्त कार्यदल गठित किया गया। 1994 में चीन में पहली बार भारत महोत्सव मनाया गया। व्यापारिक समझौते के तहत शिपकी दर्रे होते हुए सीमापार दोनो देशो के मध्य व्यापार शुरू किया गया। सन 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग झेमिन ने भारत की यात्रा की। वार्ता मे प्रमुख रूप से भारत–चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों से सम्बद्ध संधि सम्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त हाँगकांग में 1997 में दोनो देशो के बीच विमान सेवा का समझौता हुआ। किन्तु सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों में तब तनाव आ गया, जब 1998 में भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण किया तथा कारगिल संधर्ष भी भारत–पाक के मध्य हुआ। इसके अलावा दलाईलामा करमापा ने भारत में शरण ली तथा प्रधानमंत्री वाजपेई से भी मुलाकात की। चीन ने अमेरिका के साथ मिलकर भारत के परमाणु परीक्षण का तीव्र विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास कराके भारत पर एनपीटी एवं सी टी वी टी पर हस्ताक्षर कराने का दबाब बनाया। कहा कि ऐसिया में हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलेगा। चीन ने भारतीय सीमा पर अणु अस्त्रों से लैस मिसाइले तैनात कर दी। इसके अतिरिक्त चीन ने कहा कि दलाईलामा करमापा को भारत शरण न दे। यह पंचशील सिद्धान्त व सह अस्तित्व का उल्लंघन है।

इस तनाव के माहौल में विदेशमंत्री जसवंत सिंह ने चीन की यात्रा की और कारगिल पर अपना स्पष्टीकरण दिया और नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने का प्रयास किया। इसी समय जून 2000 में राष्ट्रपति के आर नारायपान ने भी चीन की यात्रा की और चीन को आश्वासन दिया कि दलाई लामा को भारत धार्मिक गुरू मानता है। उसे चीन विरोधी भारत में कोई गतिविधि नहीं करने दी जायेगी। दोनो देश के राष्ट्रपतियों ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए विशिष्टजन दल गठित करने की सहमती दी। परमाणु परीक्षण तथा ताइवान मुद्धे पर दोनो शांत रहें। राष्ट्रपति झियांग झैमिन ने कहा पारस्परिक समायोजन व सद्भाव से सीमा विवाद भी निपट जायेगा। सन् 2000 में ही दोनों देशो की नौ सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास किया गया। भारत–चीन के मध्य बढ़ते व्यापारिक सम्बन्धों ने तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चीनी माल की खपत के लिए भारतीय बाजार एक उपयुक्त क्षेत्र था। उस समय तक शिपकी दर्रा तथा लिपुलेख दर्रा व्यापार के लिए खोल दिये गये थे। सन् 2002 में चीन के प्रधान मंत्री झू रोंगजी ने 140 सदस्यों के शिष्ट मण्डल के साथ भारत की यात्रा की। शिखर वार्ता में छः सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, बाहय अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण कार्यो में उपयोग के लिए मिलजुलकर कार्य करने, पर्यटन क्षेत्र में सहयोग करने तथा ब्रहमपुत्र नदी में बाढ़ के दौरान भारत को सूचना देने की सहमतियाँ आदि सामिल थे तथा आतंकवाद के मामले में भी भारत का चीन सहयोग करेगा। इसी वर्ष विदेशमंत्री जसवंत सिंह ने भी चीन की यात्रा की और सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद मिटाने सम्बन्धी बात हुई। सन् 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री बाजपेई ने चीन की यात्रा की। इस दौरान 10 समझौता पर हस्ताक्षर किये गये। इसमें दोनो देशो के मध्य व्यापक सहयोग एवं सम्बन्धों पर पंचशील, समानता, एसिया एवं विश्व में शांति बनाये रखने, एक दूसरे के विरूद्ध शक्ति प्रयोग न करने और न ही प्रयोग की धमकी देने तथा सीमा विवाद को शांति पूर्ण वार्ताओं के द्वारा सुलझाने पर सहमति हुई। इसमे तिब्बत के प्रश्न पर भारत ने चीन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इसमें चीन ने सिक्किम के रास्ते व्यापार करने की सहमति भी दी थी। इसके साथ ही विकासशील राष्ट्रो के सहयोग के लिए भी सहमति बनी। इससे एक ओर सिक्किम के नाथुला दर्रे के माध्यम से व्यापार शुरू करके व्यापार को बढ़ावा देना था, दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से चीन ने सिक्किम को भारत का अंग मान लिया जो महत्वपूर्ण पहलू था। इसी क्रम में 2004 में चीन द्वारा प्रकाशित ''वर्ल्ड अफैयर ईयर बुक 2004'' में सिक्किम को भारत का अंग दर्शाया गया था। जो भारत की कूटनीतिक जीत थी। अप्रैल सन् 2005 में चीन के प्रधानमंत्री बेन जियावाओं ने भारत की यात्रा की और 12 सूत्री समझोते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें आपसी विवाद सुलझाने, सहयोग, व्यापार बढाने, नाथुला दर्रे से व्यापार की समीक्षा करने, आई.टी. क्षेत्र में भारत तथा हाईवेयर में चीन मिलकर कार्य करने पर विश्व में इस क्षेत्र में एकाधिकार किया जा सकता है। यह भी सहमति बनी कि सीमा के पास दोनो देश सैन्य गतिविधि नहीं बढायेंगे। साझा कारोबार को भी 20 अरब डालर तक पहुचाने का लक्ष्य रखा। विमान सेवाए भी बढायेंगें। इसके अतिरिक्त उर्जा सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु दोनों मिलकर तीसरे देश में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस खोज हेतु सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। भारत–चीन सम्बन्धों को आगे बढ़ाते हुए नबम्बर 2006 में चीन के राष्ट्रपति हूजिन्ताओं ने भारत की तीन दिवसीय यात्रा की। यह यात्रा दोनो देशो के मध्य आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों के नयें दौर की शुरूआत मानी गई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हैदराबाद हाउस में हुई बैठक के बाद चीन के राष्ट्रपति ने आपसी सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए भारत–चीन सीमा विवाद के शीघ्र समाधान एवं परस्पर व्यापार को बढ़ाने की मंशा व्यक्त की थी। संयुक्त घोषणा पत्र में 10 सूत्रीय रणनीति पर सहमत हुए–

1. भारत में कोलकत्ता और चीन में गुआंगझ में वाणिज्य दूतावास खोलेंगे।
2. 2010 तक द्विपक्षीय व्यापार को 40 अरब तक पहुंचायेगे।
3. तेल व प्राकृतिक गैस सहयोग सहमति पत्र को क्रियान्वन किया जावेगा।
4. सूचना और संचार तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करेंगे।
5. सीमा सहित प्रमुख मुद्दों पर मतभेदों को शांति पूर्ण, निष्पक्ष, तार्किक पारस्परिक स्वीकार्य ढंग से सुलझायेंगे।
6. विज्ञान और तकनीक में सहयोग को बढ़ावा देगें।
7. सांस्कृतिक सम्बन्धों एवं व्यक्तियों के बीच आदान–प्रदान बढ़ाने के लिए भारत में चीन महोत्सव तथा चीन में भारत महोत्सव आयोजित करेंगें इसके लिए आदान–प्रदान फाउण्डेशन स्थापित करेंगे।
8. पर्यटन विकास द्वारा 2007 वर्ष को भारत–चीन मित्रता वर्ष मनायेंगे।
9. विश्व व्यापार संगठन में सहयोग बढायेंगे।
10. 2007 से भारत–चीन के मध्य हॉट लाईन सेवा शुरू कर दी गई।

इससे व्यापार एवं दोनों के मध्य विश्वास मजबूत होगा। इसके अलावा सम्बन्धों में सौहार्दता लाने के लिए फरवरी 2007 में भारत, चीन तथा रूस के विदेशमंत्रीयों प्रणव मुखर्जी, झाओंझियांग तथा लॉवरॉव के बीच वार्ता आयोजित हुई और तय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों को बहुपक्षीय आधार पर सुलझायेंगे। किन्तु इसी समय भारत–अमेरिका के बढ़ते सम्बन्धों तथा भारत–अमेरिका के बीच परमाणु समझौते के कारण चीन ने भारत की आलोचना शुरू की और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु तकनीक सप्लाई देशों के संगठन ग्रुप में सम्मिलित किये जाने को प्रतिबंधि करने का समर्थन किया। चीन ने इसे शस्त्रास्त्र होड़ को बढ़ावा देना बताया। इस प्रकार भारत–चीन के सम्बन्धों में बाधा आने लगी। भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जुलाई 2007 में तथा 2008 में चीन की यात्राऐं की जिससे तनाव कम हुआ और दोनों देशों के बीच समझौते में भारत–चीन के बीच 21वीं शदी के लिए एक साझा विजन को जारी किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 10 अन्य दस्तावेजों पर

हस्ताक्षर किये तथा बाढ़ के दौरान ब्रहमपुत्र नदी के जल स्तर सम्बन्धी सूचना चीन द्वारा भारत को दिये जाने का भी समझौता हुआ। चीन ने भी यह संकेत दिया कि वह परमाणु तकनीक सप्लाई करने वाले देशो के संगठन (NSG) में भारत–अमेरिका परमाणु समझौते का समर्थन करते हुए भारत पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकुश हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करेगा। दोनो देशों के द्विपक्षीय व्यापार को 2010 तक 60 अरब डालर तक बढाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त रेल, आवास, भूविज्ञान, भू संसाधन प्रबन्धन आदि क्षेत्रों में सहयोग के हस्ताक्षर किये गये थे। 2010 में भारतीय राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा पाटिल ने चीन की यात्रा की और चीन को भारत की सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता की दावेदारी के लिए नरम रूख अपनाने को सहमत हुआ था। सन् 2010 में चीन के प्रधानमंत्री बेनजियावाओं भारत की यात्रा पर आये। यह वर्ष भारत–चीन राजनयिक सम्बन्धों की 60वीं वर्षगांढ का था। इस वर्ष भारत में चीन महोत्सव तथा चीन में भारत महोत्सव मनाया गया। यात्रा के दौरान क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर शिष्ट मण्डल स्तरीय वार्ता हुई एवं एक दूसरे के सहयोग की सहमति बनी। इसी वर्ष भारत के युवाशिष्टमण्डल के साथ खेल व युवा कार्यमंत्री ने और मानव संसाधन मंत्री एवं सड़क परिवहन मंत्रीयों ने चीन की यात्राऐं की थी। इसमें शिक्षा, खेल, सड़क अवसंरचना में चीन के सहयोग की सहमति मिली। इसके अतिरिक्त चीनी युवाशिष्टमण्डल ने भी भारत की यात्रा की। वर्ष 2011 को ''भारत–चीन आदान–प्रदान वर्ष'' मनाया गया तथा 2012 को ''भारत–चीन मैत्री वर्ष'' के रूप में मनाया गया। इन वर्षो में विकास सम्मेलन तथा आसियान सम्मेलनों में दोनो देशों के प्रमुख मिले व वार्ता की थी। सन् 2013 के मई में चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग भारत की यात्रा पर आये और 8 विभिन्न सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें व्यापार घाटे को कम करने के लिए तथा ब्रहमपुत्र नदी के मुद्दे महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा दोनों ने इच्छा व्यक्त की कि 2015 तक आपसी व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जायेगें। वार्ता से पूर्व में चीनी सैनिकों की सीमा पर घुसपैठ की घटनायें हुई थी। इसलिए नियंत्रण रेखा के प्रबन्धन में सुधार की बात हुई। ब्रहमपुत्र जलस्तर की सूचना देने पर सहमति हुई थी। स्टेपल बीजा की समस्या पर विशेष कार्यदल गठित किया जायेगा। तब तक यही बीजा व्यवस्था चलता रहेगा। दक्षिण चीन सागर में यातायात पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा। अक्टूबर 2013 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीन की यात्रा की। इस यात्रा में सीमा पर बार–बार होने वाले तनाव मुद्दे के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में दोनों देशो के सम्बन्ध बढें है। सीमा सुरक्षा समझौते पर रक्षा सचिव आर के माथुर तथा समकक्ष जिनगेवों ने हस्ताक्षर किये। डॉ. मनमोहन ने बताया की सीमा रक्षा का समझौता सम्बन्धों का मील का पत्थर है। इसमें तय हुआ कि दोनों देशों के रक्षा मुख्यालयों के बीच हॉट लाईन स्थापित की जायेगी। 4000 कि.मी. लम्बी सीमा नियंत्रण रेखा के सभी सैक्टरों पर तैनात जवानो के लिए बैठक स्थल बनाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक–दूसरे के गस्ती दलों का पीछा नहीं करेंगे तथा आमना–सामना होने पर संयम बरतेगे। अन्य मुद्दों में नदी प्रबन्धन, दोनों देशो के तीन बड़े शहरों यथा दिल्ली–बीजिंग, बैगलौर–चेंगदू तथा कोलकत्ता–कुमिंग के मध्य ''सिस्टर सिटी रिलेशनशिप'' की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त सड़क, राजमार्ग परिवहन सहयोग, विद्युत उपस्कर सेवा केन्द्र स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय सहयोग, सांस्कृतिक आदान–प्रदान आदि पर समझौता हुआ तथा वैश्विक समस्याओं यथा जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे आदि सहमतियाँ वनी।

2014 के बाद भारत–चीन सम्बन्ध

सितम्बर 2014 को चीन के राष्ट्रपति झी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनो देश इस बात पर सहमत हुए कि सीमा–विवाद का ऐसा समाधान किया जाय जो न्यायसंगत एवं तर्क संगत होने के साथ ही दोनो पक्षों को स्वीकार्य भी हों। यात्रा के दौरान 16 प्रकार के समझोते हुए यथा– कैलाश–मान सरोवर के लिए नाथुला होते हुए वैकल्पिक मार्ग हो सकता है, रेल्वे सैक्टर की परियोजना, पंचवर्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम, कस्टम मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहयोग, अन्तरिक्ष संगठनों के बीच सहयोग, सांस्कृतिक मंत्रालयों के बीच सहयोग, मुम्बई–संघाई के बीच सिस्टर सिटी का समझौता, अहमदाबाद–क्वांगचाओं के बीच सिस्टर सिटी का समझौता, गुजरात और क्वांग तुंग के बीच सिस्टर राज्य समझौता तथा गुजरात व महाराष्ट्र में औधोगिक पार्क स्थापना समझौता आदि किये गये। इसके अतिरिक्त पूर्व के सिस्टर सिटी समझौते व नदी प्रबन्धन, सड़क परिवहन आदि कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने पर सहमति हुई थी। मई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की और दोनो देशों के मध्य 24 समझौते हुए। इसी क्रम में भारत और चीन की कम्पनियों के मध्य भी अनेक समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के निवेशको को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया तथा चीनी नागरिको को ई–बीजा देने की भी घोषणा की थी। जून 2017 में दोनो देशों के बीच डोकलाम विवाद चला जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाली ''मुर्गी की गर्दन'' क्षेत्र जो सिक्किम, भूटान व चीन की सीमा पर स्थित है। चीन यहाँ अपनी सड़क का निर्माण करना चाहता है। ऐसा होने पर पूर्वी राज्यों से भारतीय सम्पर्क 20km चौड़ा मार्ग कभी भी बंद किया जा सकेगा व भूटान के लिए भी खतरा बनेगा। भारत ने इसका तीव्र विरोध किया। विवाद 73 दिन तक चला। सितम्बर 2017 में भारतीय प्रधान मंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिये चीन की यात्रा की। यह डोकलाम विवाद के बाद चीन के राष्ट्रपति के साथ पहली वार्ता थी। वार्ता में दोनो नेताओं ने स्वीकार किया कि सीमा पर शांति और अच्छे रिस्ते दोनो देशो के हित में है। डोकलाम विवाद को दर किनार करते हुए दोनो नेताओं ने सीमा पर ऐसे किसी गतिरोध से बचने के लिए सेनाओं के बीच सम्पर्क एवं संवाद मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की थी। सीमा पर होने वाले विवादों को द्विपक्षीय रिस्तो पर हावी न हाने देने के लिए

सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति जिनपिंग ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नीतियों को दुरूस्त करने व तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया था। ब्रिक्स सम्मेलन में घोषण की कि आतंकवादी संगठनों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा आतंकवाद को सहयोग करने वाले देशों के ऊपर शिकंजा कसा जायेगा।

अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर गये तथा वुहान शहर में दोनो देशो के नेताओं के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता हुई। जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले जटिल मुद्दों के समाधान के लिए सहमति बनाना था। वार्ता में सहमति बनी कि भारत–चीन मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में स्थिरता के कारक है। किसी भी मतभेद को विवाद का कारण नही बनने देंगे तथा वैश्विक मामलों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोनो नेताओं ने माना कि भारत–चीन दो विशाल अर्थव्यवस्थाऐं एवं महत्वपूर्ण शक्तियाँ है। दोनो के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर व संतुलित रिस्ते वैश्विक अनिश्चितता के बीच सकारात्मक कारक सावित हो सकते है। वार्ता में दोनो देशों के सम्बन्धें की समीक्षा की गई तथा सीमा विवाद के सम्बन्ध में सीमा से सम्बन्धित विषय पर कार्य कर रहे विशेष प्रतिनिधियों द्वारा किये जा रहे कार्यों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त सीमा पर सेनाओं द्वारा भरोसा बनाये रखने के लिए कहा। भारत–चीन दोनों देशो ने विकास और आर्थिक प्रगति द्वारा विश्वशांति में योगदान दिया है। दोनो ही वैश्विक विकास के लिए इंजिन की तरह कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा वैश्विक समृद्धि व सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, खाद्य सुरक्षा मामलों पर संयुक्त रूप से रचनात्मक कार्य करते रहेगें। आतंकवाद दोनो देशों के लिए खतरे है। इसके विरूद्ध कार्यो में सहयोग करेंगे। अफगान में संयुक्त विकास कार्यक्रमों को लागू करने पर भी सहमति बनी थी। राष्ट्रपति झी जिनपिंग ने कहा कि दोनो देश अच्छे पड़ोसी व मित्र के रूप में सकारात्मक सहयोग करते रहेगें। जून 2018 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भी दोनो नेताओं के मध्य पुनः वार्ता हुई थी। अनौपचारिक वार्ताओं की दूसरी शिखरवार्ता 11–12 अक्टूबर 2019 को महावलिपुरम (चैन्नई भारत) में हुई। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने दो दिवसीय भारत की यात्रा की थी। इस अनौपचारिक वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार निवेश, धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद आदि मुद्दों के अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं वैश्विक महत्व के दीर्घ कालीन व रणनीतिक मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान भी हुआ। दोनो ने राष्ट्रीय विकास के प्रति भी अपने दृष्टिकोण रखे। साथ ही 2018 की बुहान अनौपचारिक वार्ता की सहमतियों को भी दुहराया गया। समुद्री मार्ग से जोड़ने के लिए तमिलनाडु तथा चीन प्रान्त फुजियान के मध्य ''सिस्टर राज्य सम्बन्ध'' शुरू करने की सहमति भी बनी तथा इन प्रान्तों के सम्बन्धों के अध्ययन के लिए महाबलीपुरम में एक अकादमी स्थापित की जायेगी। दोनो देशों के सम्बन्धों की 70वीं वर्षगांढ के उपलक्ष्य में ''वर्ष 2020 को'' भारत–चीन सांस्कृतिक सम्बन्ध और लोगो के बीच आदान–प्रदान वर्ष के रूप में मनाने की सहमति बनी। आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों को बेहतर, संतुलित बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय आर्थिक एवं व्यापारिक संवाद तंत्र की स्थापना की जायेगी। सीमा विवाद निपटाने के लिए और नये उपायों को भी ढूँढा जायेगा। इसके अतिरिक्त दोनो देशों की कम्पनियों के बीच आपसी सहयोग निवेश समझौता हुए।

सन् 2001 के बाद भारत–चीन के सम्बन्धों में निरन्तर प्रगति हुई है। 2006 के बाद आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व तकनीक क्षेत्र के सम्बन्ध उच्च स्तर पर पहुच चुके है। आयात–निर्यात का क्रम बढ़ता ही जा रहा है। अनेक चीनी कम्पनियाँ भारत में अपना निवेश बढ़ा रही है। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनो देशों के मध्य व्यापार 3 अरब डालर से 80 अरब डालर के लगभग पहुँच गया है। चीन के निर्यात का भारत तीसरा बडा निर्यात बाजार बन गया है। वही भारत में चीन से सबसे अधिक आयात किया जा रहा है। भारत मुख्यतः इलेक्ट्रानिक, मैकेनीकल, कार्बनिक रसायन तथा दबाओं का कच्चमाल आदि आयात करता है। वही भारत खनिज ईधन, कपास आदि निर्यात करता है। चीन की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मोबाइल मार्केट, दिल्ली मैट्रो निर्माण, सोलर मार्केट, थर्मल पावर, पावर सैक्टर उत्पाद आदि क्षेत्रो में कार्य किये जा रहे है। किन्तु दूसरी तरफ दोनो देशों के मध्य बढ़ रहे व्यापार में भारत का व्यापार घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में प्रतिवर्ष का व्यापार घाटा 30 विलियन के करीब हो रहा है। जो भारत की दृष्टि से चिंता का विषय है। यद्यपिं दोनो देशों के बीच हुई कुछ वार्ताओं में इसे सुधारने की बात भी हुई है। किन्तु अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठायें गये है। यह सही है कि आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व तकनीकि क्षेत्र में चीन के साथ भारत के सम्बन्ध बढे है। किन्तु जब सामरिक व सीमा विवादों पर दृष्टि डालते है तो आज भी भारत के बड़े क्षेत्र को दबाये बैठा है तथा चीन अक्साई चीन के 37000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दबायें बैठा है तथा पूर्वी सीमा की मेकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता है और अरूणाचल, सिक्किम सहित 90000 वर्ग मील क्षेत्र पर आज भी अपना दाबा करता है तथा मध्यक्षेत्र की सीमा के 2000 वर्ग मील क्षेत्र पर भी अपना दाबा करता है। आये दिन सीमा पर तनाव हो जाता है। 2017 को डोकलाम विवाद, स्टैपल बीजा विवाद जिसमें कश्मीर तथा अरूणाचल के नागरिकों को सामान्य बीजा नहीं दिया जाता है। सीमा विवाद सुलझाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। विभिन्न वार्ताओं के दौरान शांति बनाये रखने व भविष्य में समाधान करने के आश्वासन दिये जाते रहे है। बीच–बीच में कभी भी तनाव पैदा कर दिया जाता है। चीन का उद्देश्य भरतीय बाजार से लाभ कमाना तथा अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में खपाना है। अच्छे सम्बन्ध संदेह के घेरे में बने हुए है। ब्रहमपुत्र नदी को लेकर भी भारत–चीन के मध्य विवाद उठ रहा है। चीन इस नदी पर एक विशाल बाँध बनाकर उसके पानी को अपने कोबी द्वीप की ओर मोड़ना चाहता है। जांग्मू में 510 मेगावाट की पन बिजली परियोजना के अलावा, चीन तिब्बत के डागू, जियाचा और जैक्सू में भी तीन बांध बना रहा है। इससे ब्रहमपुत्र नदी भारत के लिए एक बरसाती नदी बनकर रह जायेगी। इससे अरूणाचल प्रदेश तथा

असम के क्षेत्र को पानी व सिचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पायेगा। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की अधिकतर जनसंख्या की आजीविका इसी नदी पर निर्भर है। भारत ने उक्त बांधों का विरोध चीन को जताया है किन्तु चीन ने इस पर कोई ध्यान नही दिया है। इसके अतिरिक्त चीन अपने को सामरिक दृष्टि से मजबूत करने में लगा हुआ है। पाक के साथ गठजोड़ करके कराकोरम क्षेत्र का बड़ा भू भाग पाक ने चीन को सौप दिया है। कराकोरम से पाक के ग्वादार बंदरगाह तक रेल व सड़क मार्ग का निर्माण कर रहा है तथा ग्वादार का आधुनिकीकरण करने में लगा हुआ है। इससे अरब सागर पर चीन की पकड़ हो जायेगी। इसके अतिरिक्त चीन पाक का परमाणविक शस्त्रीकरण करने लगा हुआ है। पाक चीन के साथ मिलकर जे एफ 17 थंडर लड़ाकू हवाई जहाज बना रहा है। जिससे परमाणु हथियार गिराये जा सकते है। भारत के द्वारा इसका निरंतर विरोध किया गया है किन्तु चीन पर इसका कोई असर नही है। पाक–चीन गढ़जोड में रूस को भी जोड़ने के प्रयास किये जा रहे है, क्योकि कुछ समय से भारत का झुकाव अमेरिका की ओर हुआ है। भारत की घेराबंदी करते हुए चीन ने भारत के चारों ओर ''मोतियों की माला रणनीति'' को अंजाम दिया है। जिसके अन्तर्गत थाईलैण्ड में रोड़केप मूबमेंट, म्यांमार के कोको द्वीप पर चीन द्वारा निर्मित नौसैनिक अड्डा, बंगलादेश के चँटगाव बंदरगाह का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव, श्रीलंका में होटमतौड़ा बंदरगाह पर चीनी नियंत्रण, पाक के ग्वादार बंदरगाह का आधुनिकरण किया जाना तथा मालद्वीप के टापू पट्टे पर लेना एवं अफ्रीकी देशों के साथ इसी तरह के सम्बन्ध बनाने के प्रयास आदि भारत की चहुँओर से सामरिक घेरा बन्दी ही है। हिन्द महासागर में अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है। आसियान क्षेत्र के देशो के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड से आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाना आदि इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण चीन सागर के सभी छोटे–छोटे द्वीप जो पार्शेल (हरीश) एवं स्पार्टली (नानशाह) आदि पर अपना दाबा करते हुए कब्जा करता जा रहा है।

पूर्व ऐसिया प्रशांत क्षेत्र में भारत–चीन के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। भारत ने ''पूरब की ओर देखो'' तथा ''पूरब की ओर कृष्य करो'' की नीति के तहत आसियान देशो, द. कोरिया, जापान, आस्ट्रोलिया, न्यूजीलैण्ड आदि देशो के साथ सम्बन्ध बढाये है। ये देश भी चीन की एकाधिकारवादी तथा विस्तारवादी नीति से आसंकित है। दूसरी ओर चीन ने भी इस क्षेत्र में अपने आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाये है तथा हिन्द महासागर में ''मोतियों की माला'' तथा ''21 वी शताब्दी की सिल्क रूट योजना'' नीतियों के माध्यम से हिन्द महासागर में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए भारत–अमेरिका के प्रभाव को चुनौती प्रस्तुत की है। ऐसियाई क्षेत्र में चीन भारत को प्रमुख प्रतिद्वन्दी मानता है और समय–समय पर अरूणाचल, सिक्किम क्षेत्र में सीमा पर तनाब पैदा करता रहा है। पुलवामा घटना 2019 की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में चीन ने भारत को हिदायत दी कि पाक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नही की जाय, इसके लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग लेना चाहिए। चीन ने आगे कहा कि पाक समप्रभुता व अखण्डता के लिए चीन प्रतिबद्ध है। इस प्रकार व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि के साथ–साथ सामरिक व सीमा को लेकर सम्बन्ध तनावपूर्ण ही है। इतिहास में हुए घटनाक्रम (युद्ध) से सबक लेते हुए चीन जैसे विस्तारवादी देश को मित्रवत नहीं माना जा सकता है। भारत–चीन सम्बन्धों के बारे में विदेशी मामलों की स्थाई समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष शाशिथरूरं द्वारा 4 सितम्बर 2018 को प्रस्तुत की। उसकी सिफररिसों पर गौर करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में बताया कि भारत–चीन सम्बन्धों का गहन मूल्यांकन किया जाय ताकि चीन से व्यवहार के तरीकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सर्वसम्मति बन सके। चीन की पहल ''बन बेल्ट बन रोड़'' की बुनियादी परियोजना सही नहीं है क्योंकि उससे चीन–पाक आर्थिक गालियारा योजना कराकोरम से ग्बादार बंदरगाह तक, भी सम्मिलित है जो कि भारतीय अखंडता का उल्लंघन करती है। भारत को बॉर्डर पर स्वयं की कनेक्टिविटी परियोजना बनानी चाहिए क्योंकि चीन से लगी भारतीय सीमाओं पर रोड़ एवं संचार व्यवस्था सही रूप से विकसित नही हो पाई है। दोनो देशों के मध्य रक्षा सहयोग बना रहना चाहिए। जो डोकलाम विवाद के बाद बाधित हुआ है। डोकलाम विवाद का त्रिजंक्सन क्षेत्र में चीन का अतिक्रमण 2012 को चीन–भूटान समझौते का उल्लंघन है। इसमें सीमा निर्धारण के समय तीसरे देश से परामर्श की शर्त निहित थी। भारत को सीमा के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था अच्छी तरह विकसित करनी चाहिए, इसके लिए ठोस प्रयास करें। आपात काल के दौरान बैकअप के लिए सड़क निर्माण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। डोकलाम विवाद क्षेत्र में चीन ने अपनी कार्यवाही रोकी नहीं है। इस पर चिंता करने व ध्यान देने की आवश्यकता है। चीन–भारत के मध्य अभी तक स्पष्ट सीमा रेखा निर्धारित नहीं हो पाई है। अतः यह सिफारिस की गई कि स्पष्ट सीमा अनुबंध समझौता करने के लिए ठोस कदम उठाये जाये।

वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। जिसकी शुरूआत चीन से हुई थी। दूसरी तरफ चीन–अमेरीका के बीच तनाव बढ़ रहा है। जो कि विश्व को शीतयुद्ध की ओर धकेलने का संकेत देता है। विश्व स्तर पर अपना–अपना वर्चस्व स्थापित करने की आर्थिक एवं सामरिक प्रतिस्पर्धा है। चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग के प्रति आंतरिक असंतोष भी बढ़ा है। पुनः अपनी साख बढ़ाने के लिए हॉल ही में भारतीय सीमाओं पर यथा ''पैंगोग सो झील'', ''गलवान घाटी'' के साथ–साथ लद्दाख से जुडी हुई ''एल ए सी'' पर चीनी सेना ने घुसपैठ शुरू कर दी है। इससे भारत–चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। अनेक बार दोनो देशों के सैनिकों के बीच झड़पे भी हुई है। वर्तमान में नेपाल में साम्यवादी सरकार है। चीन के इसारे पर नेपाल भी भारत को सीमा विवाद पैदा करके आखे दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत अभी तक संतुलन की नीति अपनाता रहा है। एक ओर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो–पेसिफिक में क्वाड (रणनितिक चतुर्भुज) का निर्माण किया है। जिसका छुपा हुआ उद्देश्य चीन को घेरना है।

वहीं दूसरी तरफ ''संघाई सहयोग संगठन'' (चीन, रूस, भारत) की स्थाई सदस्यता भी हॉसिल की है। यदि भारत–चीन के मध्य टकराव की स्थिति बन जाती है तो संतुलन की नीति को बनाये रखना मुश्किल होगा। चीन भारत पर दबाव बनाकर चाहता है कि भारत चीन के विरूद्ध वैश्विक स्तर पर बढ़ते ''ट्रस्ट डेफिसिट'' का हिस्सा न बने। ट्रंप की भारत को लेकर दिख रही रणनीति भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। ऐसे में भारत को बेहद समझदारी और ''इण्डिया सेंट्रिक डिप्लोमेसी'' के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत–चीन के मध्य तनाब बढ़ने का अनुमान पहले से ही संभावित था। जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर मामले में भारत सरकार द्वारा कदम उठाया गया था। चीन–पाक गठजोड़ पहले से ही था, अब उसमें नेपाल भी जुड़ता जा रहा है। चीन का जब तक स्वार्थ सिद्ध होता रहे तब तक अच्छे संबंध रखता है। पिछले 60 बर्षो के भारत–चीन संबंधों पर दृष्टि डालने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। अतः भारत को सीमाओं पर इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ पाक–चीन व नेपाल गठजोड़ को कमजोर करने की भी आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ. फड़िया, बी एल, ''अन्तर्राष्ट्री सम्बन्ध'' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा*
2. *डॉ. जोशी, आर.पी. एवं अग्रवाल अमिता ''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध'' शील सन्स प्रकाशन, जयपुर।*
3. *डॉ. सिंहल, एस.सी ''अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध'' लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।*
4. *खण्डेला, मानचन्द ''भारतीय राजनीति का भविष्य'' अरिहन्त पब्लिसिंग हाऊस, जयपुर।*
5. *इन्टर नेट, NIC, google आदि से विभिन्न रिपोर्ट*
6. *इन्टरनेट विकीपीडिया*
7. *अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण, 2019, समसामापिकी वार्षिकी*
8. *प्रतियोगिता दर्पण मासिक व वार्षिकी अगस्त 2018 का अंक*
9. *अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण, 2020, समसामापिकी वार्षिकी*
10. *हर्ष, वी.पंत, प्रोफेसर किंग्स कॉलेज, लंदन के विचार, दैनिक भास्कर 28/05/2020*
11. *डॉ. सिंह, रहीस, विदेश मामलो के विशेषज्ञ का लेख, दैनिक भास्कर 31/05/2020*
12. *गुप्ता, शेखर, एडिटर इन चीफ, द प्रिन्ट, के विचार दैनिक भास्कर, 02/06/2020*
13. *विभिन्न पत्र पत्रिकाऐं*
14. *समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति तथा दैनिक जागरण आदि।*